भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 382

शुक्रवार, 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

382. श्री नीरज डांगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के जिलों की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या पहल की गई है या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): उद्योग राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का निर्णय स्वयं करती हैं।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें/पहलें शुरू की हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, , ईज ऑफ डूइंग बिजनस, संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति तथा पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण, सार्वजनिक अधिप्राप्ति में मेक इन इंडिया आदि। विकास के अन्य उपायों में आत्मनिर्भर पैकेज, विभिन्न मंत्रालयों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरूआत, राष्ट्रीय अवसरंचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में निवेश में तेजी लाने का संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए तथा भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीम हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रूपये (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय की घोषणा की गई है जिसकी शुरूआत वित्तीय वर्ष 2021-22 से हुई है।

राजस्थान में एनआईसीडीसी नोड्स का विवरण:

राज्य का नाम	नोड का नाम	विवरण
राजस्थान	खुशखेड़ा भिवाडी नीमराणा निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए)	i. केबीएनआईआर में 558 हेक्टेयर क्षेत्र तथा जेपीएमआईए में 2659 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके कार्यों के क्षेत्र में परियोजनाओं के लागत अनुमान और संभावित रोजगार सृजन शामिल हैं। ii. केबीएनआईआर और जेपीएमआईए के लिए राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड नामक एसपीवी को निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने परियोजना एसपीवी को अभी तक कोई भूमि पार्सल हस्तांतरित नहीं किया है। iii. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के जरिए भारत सरकार (49 प्रतिशत) ने 4.9 करोड़ रूपये का प्रारंभिक इक्विटी अंशदान एसपीवी के निगमन के लिए जारी किया गया है।

*****